इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रतिवर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 2 अंक सं. : 09 अप्रैल 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वा व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्ती व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं-- 1
अर्थव्यवस्था-- 3
बीमा --3
अंतरराष्ट्रीय समाचार-- 4
सूक्ष्म वित्त -- 4
पारस्परिक निधियां-- 4
नयी नियुक्तियां--5
उत्पाद एवं गंठजोड़ --5
विनियामक के कथन -- 5
विशिष्ट घटनाएं --6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं --- 7
शब्दावली --- 7
संस्थान समाचार--7
बाज़ार की खबरें--8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

बैंकों को वित्तीय समावेशन के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ सम्बद्ध होना चाहिए

अधिकतम वित्तीय समावेशन की समय-सीमा के तेजी से निकट आते जाने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कम आय वाले परिवारों को ऋण की प्राप्ति सुगम बनाने और उपलबग्ध कराने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहलग्नता स्थापित करने के लिए कहा है। उसने बैंकों से सुसंचालित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का उपयोग कारबार संपर्कियों (BCs) के रूप में करने हेतु भी कहा है। इस समय, अनुमति होने के बावजूद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का उपयोग कारबार संपर्कियों के रूप में नहीं किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी विचार व्यक्त किया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे रणनीतिक आयोजना बनाने और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से सम्बन्धित अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए अपने आप को अग्रणी बैंक योजना (LBS) में और अधिक संलग्न करें।

बैंकों को मूल दर प्रणाली अपनाने हेतु 3 माह का और समय मिला

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को नयी मूल दर-सम्बद्ध उधार प्रणाली अपनाने के लिए मूल रूप से निर्धारित 1 अप्रैल की तिथि को तीन माह के लिए विस्तारित कर दिया है। सभी नये और 1 जुलाई, 2010 को या उसके बाद नवीकृत किए जाने वाले ऋणों की न्यूनतम दर मूल दर पर निर्धारित की जाएगी। हालांकि, मीयादी जमाराशियों पर ऋणों, कर्मचारी ऋणों तथा विभेदक ब्याज दर ऋणों के मामले में अपवाद की व्यवस्था होगी। मूल दर का निर्धारण करने से सम्बन्धित मानदंडों में जमा लागत, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) एव अनाबंटनीय उपरिव्यय लागतों से सम्बन्धित नकारात्मक प्रभार के समायोजन शामिल होंगे।

सेन्ट्रल बैंक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने हेतु डाकियों की सेवाओं का उपयोग करेगा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (CMD) श्री एस श्रीधर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंक गांवों में कार्यरत डाकियों की सेवाओं का उपयोग कारबार संपर्कियों (BCs) के रूप में करने

हेतु भारतीय डाक विभाग के साथ बातचीत कर रहा है। वित्तीय समावेशन की दिशा में एक नवोन्मेषी उपाय माना जाने वाला कारबार संपर्की मॉडल जनवरी 2006 में इसकी शुरूआत किए जाने के समय से ही वांछित प्रभाव नहीं निर्मित कर पाया है। जहां तक उन बैंकों का सम्बन्ध है, जिन्होंने वित्तीय समावेशन के लिए डाक घरों का सहयोग प्राप्त किया है, लगभग 5,200 डाक घरों को कारबार संपर्की मॉडल के बिक्री केन्द्रों के रूप में अपना कर इस दिशा में केवल भारतीय स्टेट बैंक ने ही कुछ प्रगति की है़। भारतीय रिज़र्व बैंक कारबार संपर्कियों की परिभाषा को निरंतर आधार पर विस्तारित करते हुए उक्त मॉडल में सुधार करता आ रहा है। उक्त मॉडल बैंकों को ग्रामीण जनसंख्या के अत्यधिक निकटस्थ स्थलों पर नकदी लेने और नकदी देने (cash-in-cash-out) जैसे लेनदेन करते हुए उसके द्वारा अंतिम समस्या का निराकरण करने की सुविधा प्रदान करता है।

बैंकों के पास दबाव का सामना करने की क्षमता मौजूद

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह विचार व्यक्त किया है कि पुनर्व्यवस्थित खातों के तहत ऋणों के अनर्जक आस्ति बन जाने के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र परिसम्पत्ति गुणवत्ता दबाव का सामना कर लेने की स्थिति में है । वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारतीय बैंकों को एकबारगी उपाय के रूप में इन खातों को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किए बिना ही ऋणों को पुनर्व्यवस्थिति करने की अनुमति प्रदान की गई थी। दिसम्बर 2009 के दिन मानक श्रेणी में पुनर्व्यवस्थित खाते सकल अग्रिमों के 3.1 % थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह कहा है कि "हालांकि, अब दबाव परीक्षण से यह पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र सहज रूप से लचीला है तथा समस्त पुनर्व्यवस्थित अग्रिमों के काल्पनिक रूप से अनर्जक आस्ति बन जाने के बावजूद, यह दबाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।"

वित्तीय समावेशन की जांच करने का सूचकांक जून से

वित्त मंत्रालय जून और उसके बाद से वित्तीय समावेशन का तिमाही आधार पर मूल्यांकन करने हेतु एक सूचकांक का उपयोग करेगा। यह जनसंख्या के अपेक्षाकृत एक विशाल वर्ग को औपचारिक वित्तीय बाज़ारों के साथ एकीकृत करने में निश्चय ही सहायता करेगा। उक्त सूचकांक परिवारों को प्राप्त वित्तीय समावेशन सुविधा की सीमा का मूल रूप से वित्तीय मध्यवर्तियों के साथ उनके व्यवसायों, मुख्य वित्तीय सेवाओं की पात्रता एवं उनकी वहनीयता को ध्यान में रखते हुए पता लगाएगा। यह वित्तीय समावेशन की स्थिति और एक समयावधि में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए सापेक्ष सुधारों का आकलन करने में सहायता करेगा, जिससे सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय समावेशन को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सामयिक एवं क्षेत्र-विशिष्ट उपाय करने का अवसर प्राप्त होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समावेशी अभियान को कृषि स्नातक संचालित करेंगे

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संकेन्द्रित नियुक्ति के माध्यम से उनकी वित्तीय समावेशन की कार्यसूची को बढ़ावा दिए जाने हेतु सुसज्जित होने के परिणामस्वरूप इन दिनों कृषि स्नातकों की मांग अत्यधिक बढ़ गई

है। पंजाब नैशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने परिचालन को विस्तारित करने के लिए कृषि अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य पहले से ही आरंभ कर दिया है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री बी.एस. बिष्ट का कहना है कि "हमारे विद्यार्थी ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं, विशेषत: कृषि से सम्बन्धित आवश्यकताओं को समझते हैं और यह स्थिति उन्हें राष्ट्रीयकृत एवं निजी, दोनों ही प्रकार के बैंकों के लिए एक आकर्षक प्रस्थापना बना देती है।" इस वर्ष विश्वविद्यालय परिसर में संचालित साक्षात्कारों के माध्यम से लगभग 100 विद्यार्थियों को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अधिकाधिक कृषि उधारों पर सरकार द्वारा बल दिए जाने के अनुरूप है। इस वर्ष सरकारने 4 % की कृषि वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, जो आगामी वित्तीय वर्ष में 8.5 % की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के उसके प्रयासों की सफलता का मूल मंत्र है।

सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया

सरकार ने अधिमान शेयरों, बोनस शेयरों और निजी तौर पर शेयर आबंटन के माध्यम से बाज़ार से पूंजी जुटाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त विधेयक में भारतीय स्टेट बैंक में सरकार की न्यूनतम शेयरधारिता को विद्यमान 55 % से घटा कर 51 % किए जाने का प्रस्ताव है। उक्त विधेयक में सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से उसे बढ़ाने या घटाने में समर्थ बनाते हुए भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा कर 5,000 करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।

पैनल ने साख निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अधिक प्रकटन की पैरवी की

एक सरकारी पैनल ने यह निर्णय दिया है कि साख निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अब विशेषत: उन मामलों, जहां हितों का टकराव होता हो, अर्थात् ऐसी एजेन्सियों की सहायक कम्पनियों द्वारा वसूल किए गए शुल्कों के सम्बन्ध में राजस्व के व्योरे प्रकट किए जाने चाहिए। उक्त पैनल ने इस बात को नोट किया है कि "साख निर्धारण एजेन्सियां (CRAs) जिन निर्गमकर्ताओं की साख का निर्धारण करती हैं उन्हें परामर्शी एवं अनुसंधान सेवाओं जैसी अनुषंगी सेवाएं भी प्रदान करती हैं। हालांकि, उन्हें ऐसा कोई भी कारबार संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिसका साख निर्धारण के कार्य के साथ हितों का टकराव होता हो।" उक्त पैनल ने इसके अलावा यह भी कहा है कि हाल ही के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में साख निर्धारण की गुणवत्ता के सूक्ष्म जांच के अधीन आ जाने के परिणामस्वरूप विनियामकों और निर्गमकर्ताओं को आवश्यक रूप से यथोचित कर्तव्यपरायणता बरतनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसने यह भी सिफ़ारिश की है कि साख निर्धारण एजेन्सियां जिन कम्पनियों / संस्थाओं का श्रेणी निर्धारण करती

हैं, उनसे प्राप्त प्रतिकर (मुआवजे) के स्वरूप को प्रकट करें तथा अपनी साख निर्धारण की कार्यप्रणालियों में अन्तर्निहित मान्यताओं से सम्बन्धित सूचना को भी प्रकाशित करें।

बाह्य अलंकरण को अलविदा : बैंक अब और अधिक प्रकटन करेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से मार्च 2010 में समाप्त वर्ष के तुलन पत्र में लेखा-टिप्पणियों में कई प्रकार के (उदाहरण के लिए जमाराशियों, अग्रिमों, ऋण जोखिमों (expsures) तथा अनर्जक आस्तियों (NPAs) के संकेन्द्रण जैसे) विवरण देने के लिए कहा है, जिनसे पारदर्शिता के स्तर में प्रचुर रूप से वृद्धि हो जाएगी। जमाराशियों के संकेन्द्रण से सम्बन्धित प्रकटन में 20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों तथा बैंकों की कुल जमाराशियों की तुलना में उनकी जमाराशियों के प्रतिशत का समावेश होगा। विशिष्ट रूप से संसाधन के लिए फैले हुए बैंक और अपने तुलन पत्र को विस्तारित करने के इच्छुक बैंक ऐसे जमा प्रमाण पत्र जारी करते हुए निधियां जुटाते हैं, जिन पर पर्याप्त रूप से अधिक ब्याज दर प्रदान करनी होती है। इन निधियों को सक्रिय खज़ानों (Treasuries) वाली कम्पनियों के पास कम ब्याज दर पर अभिनियोजित किया जाता है। जहां इस प्रकार के उधार से होने वाला लाभ नगण्य हो सकता है, वहीं यह बैंकों की वृद्धि के मान को प्रदर्शित करने में सहायता करता है।

भारतीय बैंक संघ की वेब साइट निर्यातकों के लिए ऋण दरों, प्रभारों को प्रदर्शित करेगी

बैंकों के साथ अपने नेमी व्यवहारों की लेनदेन लागत के बारे में मतिभ्रम से ग्रस्त निर्यातक अब निर्यात ऋण की दरों और उनसे सम्बन्धित कार्रवाई प्रभारों (जो हर एक बैंक में अलग-अलग होते हैं) से सम्बन्धित सूचना भारतीय बैंक संघ (IBA) की वेब साइट पर प्राप्त करने में समर्थ होंगे। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (FIEO) के अध्यक्ष श्री शक्तिवेल का दावा है कि "इस निर्णय से प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी। इसका परिणाम यह भी होगा कि बैंक ऋण एवं कार्रवाई प्रभार प्रतिस्पर्धी दरों पर लगाएगें।" उन्होंने कहा कि "इसके अलावा निर्यातक भी उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली दरों के आधार पर इस बात का निर्णय कर सकेंगे कि वे किस उधारकर्ता के साथ बैंकिंग व्यवहार करें।"

आईसीआईसीआई बैंक को सिंगापुर परिचालन हेतु संपूर्ण लाइसेंस प्राप्त

आईसीआईसीआई बैंक को मॉनिटरी अथॉरिटी, सिंगापुर द्वारा उसकी सिंगापुर शाखा में अर्हता प्राप्त संपूर्ण बैंकिंग (QFB) सुविधा प्रदान कर दी गई है। उक्त हैसियत आईसीआईसीआई बैंक को उक्त क्षेत्र में पूर्ण स्तरीय कारबार करने और कुछ समय में 25 से अधिक शाखाएं स्थापित करने में समर्थ बनाएगी। इसके अलावा बैंक ने भारत में हो रहे सुदृढ़ पूंजी एवं निवेश प्रवाहों का लाभ उठाते हुए सिंगापुर और एसियान क्षेत्र में कॉरपोरेट, वाणिज्यिक, संपत्ति प्रबन्धन तथा प्रत्यक्ष बैंकिंग कारबार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान संकेन्द्रित करने की योजना बना रखी है। आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबन्ध

निदेशक श्रीमती चन्दा कोचर ने कहा है, "हमें इस क्षेत्र, जिसके भारत के साथ सुदृढ़ सम्बन्ध रहे हैं, में अपने ग्राहक आधार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किए जाने की आशा है।"

6

आर्कस्टोन का भारत में अवतरण : धनलक्ष्मी बैंक में 5 % के जोखिम (stake) अभिगृहीत किया

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित बचाव (Hedge) निधि आर्कस्टोन कैपिटल एलएलसी ने निजी रूप से स्वाधिकृत धनलक्ष्मी बैंक में 5 % के आस-पास जोखिम (stake) अभिगृहीत करते हुए भारत में अवतरण किया है। उक्त निधि ने बैंक के शेयरों को भारत में अवतरण हेतु उसकी निवेश संस्था मास्टर फंड के माध्यम से हथियाए हैं। डेन्वर स्थित बचाव (headge) निधि पिछले कुछेक वर्षों से भारत में मूल्यवान उत्पाद वाली कम्पनी में जोखिम अभिगृहीत (value buy) करने की ताक में थी।

अर्थव्यवस्था

निर्यात सवर्धन योजनाओं से 43,622 करोड़ रुपये की राजस्व हानि

निर्यात में गिरावट और रुपये की मूल्यवृद्धि को प्रतिबिंबित करते हुए निर्यात संवर्धन योजनाओं के कारण वर्ष 2009-10 में केन्द्र द्वारा गंवाए गए राजस्व के पिछले वर्ष के स्तर से 11 % के सीमान्त रूप से कम होने, किन्तु 43,622 करोड़ रुपये के रूप में तब भी काफी अधिक रहने का अनुमान है। वर्ष 2008-09 में यह 49,053 करोड़ रुपये था। अप्रैल 2009 -जनवरी 2010 की अवधि में निर्यात 7,15,764 करोड़ रुपये के मुकाबले 6,29,224 करोड़ रुपये का था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपये में मूल्य की दृष्टि से गिरावट का संकेत है। वर्ष 2009-10 में रुपये में पिछले वर्ष की तुलना में औसतन 7 % की मूल्यवृद्धि दर्ज हुई है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये में मूल्य की दृष्टि से आयात के मूल्य में कमी आई है। चूंकि लगाया गया शुल्क भी रुपये के मूल्य पर आधारित है, फलत: गंवाए गए राजस्व में में भी कमी परिलक्षित हुई है।

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि में 315 मिलियन डालर की कमी; रुपया 6 सप्ताह के उच्च स्तर पर बंद हुआ

26 फरवरी को समाप्त सप्ताह में देश की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि 315 मिलियन डालर घट कर 278.4 बिलियन डालर रह गई। जहां विदेशी मुद्रा वाली आस्तियां 212 मिलियन डालर घट कर 253.9 बिलियन डालर रह गईं, वही सोने का आरक्षित भण्डार 136 मिलियन डालर कम हो कर 17.9 बिलियन डालर हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास विशेष आहरण अधिकार 26 मिलियन की बढ़ोत्तरी के साथ 5.05 बिलियन डालर हो गए, वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधियां 7 मिलियन डालर बढ़ कर 1.39

बिलियन डालर हो गईं। हालांकि, कुल आरक्षित निधियों मे पिछले एक वर्ष में 29.1 बिलियन डालर की वृद्धि हुई है। अनिवार्यत: इन आरक्षित निधियों में विदेशी मुद्राओं, सोने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास विशेष आहरण अधिकारों का समावेश है।

7

मुद्रास्फीति सम्बन्धी चिंता सुलभ मुद्रा नीति की समाप्ति का संकेत देती है

मुद्रास्फीति पर मांग-पक्ष के दबाव में तेजी आने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक उसके गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव द्वारा यथा वर्णित रूप में निभावपरक ऋण नीति से निर्गमन की अपनी रणनीति जारी रखेगा। प्रत्यावर्ती खरीद (reverse repo) और खरीद (repo) दरों, प्रत्येक में 25 आधार अंकों (bps) की अद्यतन वृद्धि के पीछे निहित औचित्य को स्पष्ट करते हुए डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों की अधिकता (overheating) वाले जोखिम का सामना कर रही है। इसलिए, यद्यपि इससे हाल की अवधि में वृद्धि के मामूली तौर पर प्रभावित होने के बावजूद, यह वृद्धि आवश्यक है। जनवरी में केन्द्रीय बैंक ने प्रणाली में मौजूद चलनिधि को अवशोषित करने के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 75 आधार अंकों की वृद्धि की थी।

ऋण वृद्धि ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 16 % का लक्ष्य पार किया

ऋण वृद्धि वर्ष 2009-10 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 16 % के लक्ष्य को पार कर गई है। कुल ऋण और निवल खाद्येतर ऋण 12 मार्च, 2010 को समाप्त पखवाड़े में 16 % से कुछ अधिक ही बढ़े। यह 26 फरवरी, 2010 को समाप्त पिछले पखवाड़े में परिलक्षित 15.79 % के स्तर से लगभग 26 आधार अंक अधिक है। कुल ऋणों में 16.05 % की वृद्धि हुई, जबकि खाद्येतर ऋण में 16.28 % की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई। उधारकर्ताओं के पास कुल ऋणों की बकाया राशि 12 मार्च, 2010 को समाप्त पखवाड़े में 31,24,850 करोड़ रही। अपनी पिछली मौद्रिक नीति में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र के लिए अपने ऋण वृद्धि के लक्ष्य को उसके द्वारा पहले निर्धारित किए गए 18 % से घटा कर 16 % कर दिया था।

बीमा

सामान्य बीमाकर्ताओं के समक्ष अपेक्षाकृत अधिक दायित्व उपस्थित

वैश्विक पुनर्बीमाकर्ताओं ने पहली बार संधि से सम्बन्धित दायित्वों में अल्प-अभिदान करते हुए भारत के प्राथमिक सामान्य बीमाकर्ताओं से अपना मुंह मोड़ लिया है। इस प्रकार, भारतीय सामान्य बीमा कम्पनियों को इन दायित्वों को स्वयं ही वहन करना होगा तथा उन्हें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। ये अल्प-अभिदान अधिकांशत: समुद्री पोत, समुद्री माल तथा विविध दुर्घटना श्रेणियों में हैं। भारत के सामान्य बीमे में इस कारबार का अंश लगभग 20 % होता है। इन सभी कारबारों में अल्प-अभिदान 25 से लेकर 35 % तक अलग-

अलग है। निजी क्षेत्र के कारबार का कम से कम 55 % तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कारबार का लगभग 25 % सरहद-पार के बीमाकर्ताओं के हवाले है। पुनर्बीमाकर्ताओं के अल्प-अभिदान का कारण व्यापक तौर पर घरेलू बीमाकर्ताओं द्वारा उद्धृत कम जोखिम प्रीमियम है। विनियंत्रण के बाद से घरेलू सामान्य बीमा बाज़ारों में जोखिम प्रीमियमों में भारी तलोच्छेदन (undercutting) हुआ है, जिसमें वर्ष 2007 तक 80 % जितनी गिरावट आई है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक (ECB) ने मुख्य दर को स्थिर रखा

यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक (ECB) ने मुख्य दर को 1.0 % पर स्थिर रखा है, जबकि बाज़ारों ने अपना ध्यान बैंक की गैर-परंपरागत ऋण नीतियों तथा ग्रीक ऋण संकट पर केन्द्रित रखा। यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक के अध्यक्ष श्री जीन क्लाउड त्रिचर द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार बैंक अप्रैल से उसके 3-माह वाले ऋणों के मामले में सामान्य टेण्डरों की ओर वापस आ रहा है। इसके अलावा, यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक अपने साप्ताहिक परिचालनों में बाज़ार की इस आशा के अनुरूप कि बैंक किसी प्रकार की सहायता की व्यवस्था करेगा, दूसरी तिमाही में बैंकों को असीमित रकमें उधार देना जारी रखेगा।

फेडरल रिज़र्व ने कार्ड कम्पनियों से दर में बढ़ोत्तरी का पुनरीक्षण करने को कहा

अमरीकी फेडरल रिज़र्व ने क्रेडिट कार्ड कम्पनियों से ब्याज दर में वृद्धि का प्रत्येक छ: माह पर पुनरीक्षण करने तथा उच्चतर दर का कारण परिवर्तित हो जाने पर उनमें कमी करने के लिए कहा है। इस प्रकार ऋण जोखिम अथवा बाज़ार की स्थितियों जैसे दर परिवर्तन के संकेतकों में सुधार होने पर कार्ड जारीकर्ताओं को दरों में कमी करनी होगी। दर पुनरीक्षण का कार्य प्रावधान, जो क्रेडिट कार्ड विधान का ही एक अंग है, के 22 अगस्त को प्रभावी हो जाने के छ: माह बाद आरंभ होगा।

फ्रांस के सेन्ट्रल बैंक के प्रमुख ने अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की पतवार संभाली

फ्रांस के सेन्ट्रल बैंक के गवर्नर, श्री क्रिश्चियन नोयेर को आगामी तीन वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री नोयेर ने मैक्सिको के सेन्ट्रल बैंक के प्रमुख श्री गुइलेर्मो ओर्टिज़ का तात्कालिक प्रभाव से स्थान लिया है। श्री ओर्टिज दिसम्बर के अंत में सेन्ट्रल बैंक के गवर्नर के पद से मुक्त हो गए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बासेल स्थित अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के अपने पद का भी त्याग कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, जो 56 सेन्ट्रल बैंकों और मौद्रिक प्राधिकारियों का एक समूह है, की मौद्रिक स्थिरता को बढ़ावा देने और विश्व की अर्थव्यवस्था तथा उसके साथ ही साथ वित्तीय बाज़ारों पर निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के प्रबन्धन में सहायता भी करता है।

सूक्ष्म वित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने स्व-विनियामक निकाय गठित किया

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (MFIs), जिनकी शुरूआत प्रारंभ में ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक सामाजिक उद्यमवृत्ति गतिविधि के रूप में हुई थी, अब 31 बड़ी संस्थाओं द्वारा अपने आप को भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अधीन लाते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के रूप में पंजीकृत करा लिए जाने के परिणामस्वरूप पूर्ण विकसित संगठित उद्योग बन गई हैं। ये संस्थाएं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के नेटवर्क (MFIN), एक ऐसा संघ, जो उद्योग के विकास के लिए काम करेगा, का गठन करने के लिए एकजुट हो गई हैं। उधारकर्ताओं के लिए इसका अर्थ ऋणों का अधिक पारदर्शी मूल्य-निर्धारण हो सकता है, जबकि उधारदाता इस बात के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं कि सूदखोरी के स्वरूप वाला उधार नहीं दिया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का यह नेटवर्क, जिसमें भारत के सूक्ष्म वित्त उधारों के 80 % का समावेश होगा, एक स्व-विनियामक संगठन के रूप में काम करेगा। हालांकि, उक्त संघ में उन सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का समावेश नहीं है, जो एक न्यास के रूप में काम करती हैं तथा जिनका प्रयोजन लाभार्जन नहीं होता।

पारस्परिक निधियां

फरवरी में पारस्परिक निधियों की आस्तियां 2.6 % बढ़ीं

हाल के दिनों में इक्विटी बाज़ार में निवेशकों के संतुष्टि स्तर से घरेलू निधि बाजार को जनवरी की तुलना में फरवरी मे अधिक मूल निधि जुटाने में सहायता प्राप्त हुई है। भारतीय पारस्परिक निधि संघ (AMFI) के अनुसार उद्योग की प्रबन्धाधीन औसत परिसम्पत्तियां (AAUM) पिछले माह के 7,61,625.53 करोड़ रुपये के स्तर से फरवरी में 2.64 % बढ़ कर 7,81,711.52 करोड़ रुपये हो गईं। हालांकि, विद्यमान 38 निधि गृहों में से 13 ने उनकी प्रबन्धनाधीन औसत परिसम्पत्तियों में गिरावट दर्ज की है। रिलाएन्स म्युच्युअल फंड, जिसकी प्रबन्धाधीन औसत परिसम्पत्तियों (AAUM) में फरवरी में 1.28 % की मामूली कमी आई, को छोड़कर सभी शीर्ष कम्पनियों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि हुई।

स्वरूप की दृष्टि से कम अस्थिर ईटीएक निवेशकों को पसंद आई

इक्विटी बाज़ारों में विद्यमान गहन अस्थिरता को लेकर चिंतित निवेशक कतिपय खरीदारों के शेयर बाजार में क्रय-विक्रय की जाने वाली विविध निधियों (ETF) में निवेश को वरीयता दिए जाने के परिणामस्वरूप इक्विटी योजनाओं से कतरा रहे हैं। भारतीय पारस्परिक निधि संघ (AMFI) के अनुसार शेयर बाज़ार में

क्रय-विक्रय की जाने वाली निधियों की सोने सहित कुल प्रबन्धाधीन औसत परिसम्पत्तियां (AAUM) जनवरी महीने में 2,687 करोड़ रुपये थीं - जो नवम्बर, 2009 के अंत में 2,443 करोड़ रुपये से 10 % अधिक थीं। प्रबन्धाधीन औसत परिसम्पत्तियों में वृद्धि के अलावा, शेयर बाज़ार में क्रय-विक्रय की जाने वाली निधियों में निवेश करने वाले निवेशक खातों में स्थिर बढ़ोत्तरी हुई है। शेयर बाज़ार में क्रय-विक्रय की जाने वाली निधियों में निवेशक खातों में लगभग 14 % की वृद्धि हुई तथा वे पिछले वर्ष के नवम्बर में 1.43 लाख की तुलना में जनवरी में 1.65 लाख हो गए।

नयी नियुक्तियां

श्री रामदोराई बंबई शेयर बाज़ार के अध्यक्ष बनें

टाटा कन्सल्टैन्सी सर्विसेज (TCS) के उपाध्यक्ष श्री एस. रामदोराई श्री जगदीश कपूर के उक्त पद से हट जाने के बाद बंबई शेयर बाज़ार (BSE) के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष बन गए हैं।

श्री सेन यूनाइटेड बैंक के नये अध्यक्ष नियुक्त

देना बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री भास्कर सेन ने 1 मार्च से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पद का कार्यभार संभाल लिया है। श्री सेन वर्ष 1974 के परिवीक्षाधीन अधिकारी हैं तथा उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान कतिपय महत्वपूर्ण पदों का दायित्व संभाला है।

श्री वी. शंकर स्टैडर्ड चार्टर्ड बैंक के नये निदेशक नियुक्त

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने श्री वी. शंकर को 1 मई से मध्य पूर्व, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में परिचालनों के लिए अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वह दुबई में कार्यरत रहेंगे तथा मध्य पूर्व में तैनात किए जाने वाले अब तक के सर्वाधिक वरिष्ठ कार्यपालक होंगे। वर्तमान में सिंगापुर में तैनात श्री शंकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के वैश्विक कॉरपोरेट बैंकिंग कारबार के प्रधान हैं। इसके अलावा, श्री शंकर इस वर्ष 1 मई से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के निदेशक भी होंगे।

श्रीमती सुवलक्ष्मी स्टेट बैंक ऑफ मारीशस की भारतीय परिचालन की प्रधान नियुक्त

स्टेट बैंक ऑफ मारीशस ने श्रीमती सुवलक्ष्मी चक्रवर्ती को अपने भारतीय परिचालनों के प्रधान के रूप में नियुक्त किया है। इसके पूर्व वह बर्कलेज बैंक की भारत के लिए वाणिज्यिक बैंकिंग की निदेशक थीं।

उत्पाद एवं गंठजोड़

सिबिल ने 31 सूक्ष्म वित्त संस्थओं के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया

ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) ने एक सूक्ष्म वित्त ऋण आसूचना ब्यूरो प्रारंभ करने के लिए 31 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित किया है। सिबिल के प्रबन्ध निदेशक श्री अरुण ठुकराल के अनुसार इससे सूक्ष्म वित्त खण्ड में अनर्जक आस्तियों को रोकने में सहायता प्राप्त होगी तथा ऋण की पैठ में बी बढ़ोत्तरी होगी। अनुमानित रूप से सूक्ष्म वित्त क्षेत्र लगभग 120 मिलियन परिवारों तक फैला है, जो 1.2 लाख करोड़ रुपये की ऋण मांग में रूपांतरित होता है; किन्तु बहुविध उधार और अति-एक्सपोजर जैसे मुद्दे चिंता के क्षेत्र बने हुए हैं। प्रारंभ में अपनी सेवाओं के एक अंग के रूप में सिबिल सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के प्रति उधारकर्ताओं के एक्सपोजर से सम्बन्धित आकड़े उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा उसने ग्राहकों के लिए गुणांकन मॉडल विकसित करने की योजना भी बना रखी है। श्री ठुकराल कहना है कि जहां सूक्ष्म वित्त खण्ड के लिए रिकार्ड तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, वही उत्साहजनक बात यह है कि वर्तमान में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं मतदाता परिचय पत्र के आंकड़े कैप्चर करती हैं।

आईडीबीआई बैंक ने पारस्परिक निधि परिचालन की शुरूआत की

आईडीबीआई बैंक ने अपने पारस्परिक निधि (MF) परिचालन की शुरूआत की घोषणा की है। उक्त निधि गृह बाज़ार विनियामक के पास इक्विटी एवं स्थिर आय उत्पादों के लिए शीघ्र ही आवेदन करेगा। आईडीबीआई पारस्परिक निधि ब्याजहीन रूप में प्रबन्धित निधियों पर ध्यान संकेन्द्रित करना चाहती है और इसलिए वह निफ्टी पर आधारित अपनी पहली सूचकांक निधि की शुरूआत करेगी। इसके बाद सेंसेक्स पर आधारित निधि और ऋण निधियों की शुरूआत की जाएगी।

इंडियन बैंक ने वीसा कार्ड की शुरूआत की

इंडियन बैंक ने कम्पनियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक वीसा कारबार कार्ड की शुरूआत की है। उक्त कार्ड में नि:शुल्क बीमा प्रसुविधा सहित वैश्विक कार्डों से जुड़ी सभी प्रसुविधाएं उपलब्ध हैं तथा इसका मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारित किया गया है।

विनियामकों के कथन

मूल दर योजना जुलाई से लागू होगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि मूल दर योजना - ग्राहकों के लिए न्यूनतम उधार दर की गणना करने की नयी प्रणाली को कार्यान्वित करने में अप्रैल से भी अधिक का समय लगेगा। वास्तव में भारतीय बैंक संघ ने भी भारतीय रिज़र्व बैंक से उक्त समय-सीमा को तीन माह बढ़ा कर जुलाई कर देने के लिए कहा है। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों की मूल दर के 8.5 % से 9.5 % के बीच की श्रेणी, वर्तमान 11.75 - 12 % की मूल उधार दर (PLR) से कम रहने की आशा है। इस प्रक्रिया में भारतीय रिज़र्व बैंक ग्राहकों की ओर से निष्पक्षता की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेगा तथा वह पारदर्शिता के मुद्दों का निराकरण करेगा।

स्फीतिकारक उधार लक्ष्य जोखिमपूर्ण

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के उधार लेने के कार्यक्रम से किसी महत्वपर्ण चुनौती के उपस्थित होने की संभावना नहीं है, किन्तु लक्ष्य के निर्धारित स्तर से अधिक हो जाने अर्थात् निजी क्षेत्र की मांग और सरकार की उधार लेने से सम्बन्धित आवश्यकताएं अपेक्षित स्तर से अधिक हो जाने पर जोखिम पैदा हो सकते हैं। डॉ. गोकर्ण के अनुसार देश के आर्थिक पुनरुत्थान में स्थिरता आ रही थी तथा उसे व्यापक आधार प्राप्त हो रहा था, किन्तु मूल रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों द्वारा प्रेरित बड़ी मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत व्यापक अर्थव्यवस्था, विशेषत: विनिर्माण क्षेत्र में भी फैलनी आरंभ हो गई है।

निष्क्रिय नो फ्रिल्स खातों को सक्रिय किए जाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों के परिणाम सकारात्मक

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों द्वारा उनके सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी भुगतानों को इन खातों के माध्यम से किए जाने हेतु सहमत हो जाने के परिणामस्वरूप मिलियनों निष्क्रिय नो फ्रिल्स खातों को सक्रिय किए जाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों में क्रमिक रूप से प्रगति हो रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती ने यह विचार व्यक्त किया है कि कई एक राज्य सरकारें अपने भुगतान बैंकों के माध्यम से किए जाने के प्रति उदासीन हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री के.आर. आनंद का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित भुगतान नो फ्रिल्स खातों के माध्यम से किए जाने के परिणामस्वरूप अनुमानत: 1 लाख करोड़ रुपये की रकम बैंकिंग प्रणाली में जुड़ जाएगी।

बैंकिंग सुविधाओं को ग्रामीण गरीबों तक पहुंचाने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऐसे नो फ्रिल्स खाते खोलने के लिए कहा था, जिनमें किसी प्रकार की शेष राशि रखे जाने की आवश्यकता नहीं होती।

ग्रामीण खाते खोलने के लिए बैंक अनूठी परिचय पत्र संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरात ने कहा है कि बैंक ग्रामीण भारत में खाते खोलने के लिए अनूठी परिचय पत्र संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने पिछले वर्ष देश के सभी नागरिकों को अनूठे परिचय पत्र जारी करने के अधिदेश के साथ भारतीय अनूठे परिचय प्राधिकरण (UIAI) की स्थापना की थी। ग्रामीण भारत में अनूठे परिचय पत्र से खाते खोलने के कार्य को सुगम बनाने का यह निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक के समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों अथवा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच न रखने वाले बैंकिंग सुविधा रहित लोगों को वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के अभियान के अनुरूप है। श्रीमती थोरात ने यह मत व्यक्त किया कि "अनूठे परिचय पत्र को बैंक खातों से सम्बद्ध किए जाने के निर्णय को ग्रामीण भारत के मामले में बैंक के अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंडों के अनुपालन के रूप में माना जा सकता है।" यह भी उल्लेखनीय है कि बैंकों ने ग्रामीण भारत में सूक्ष्म एटीएम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जो मूल एटीएम कार्यों को करेगा और तब भी शहरी केन्द्रों में स्थापित सामान्य एटीएमों की अपेक्षा सस्ती लागतों पर स्थापित किया जा सकेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक 10 रुपये के (बहुलक) पोलिमर नोट जारी करेगा

कनाडा और आस्ट्रेलिया के पदचिन्हों पर चलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही उनके आयुकाल को बढ़ाने तथा जालसाजों को विफल करने के लिए (भारत में) 10 रुपये के मूल्यवर्ग वाले 100 करोड़ (बहुलक) पोलिमर नोट जारी करेगा। इन नोटों को प्रारंभ में पांच शहरों में जारी किया जाएगा। इन पोलिमर नोटों की वातावरणपरक-अनुकूलता के बारे में बात करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है, "पोलिमर नोटों के अपेक्षाकृत लम्बे जीवनकाल तथा पुन: चालन के प्रति उनकी आज्ञाकारिता को ध्यान में रखते हुए कागज़ के बैंक नोटों की तुलना में पोलिमर नोटों के 'कार्बन फूटप्रिंट'के अधिक टिकाऊ होने की संभावना है। लिहाजा, यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसका हम प्रायोगिक चरण में अध्ययन करेंगे तथा पोलिमर नोटों के बारे में दीर्घावधिक आधार वाले उपक्रम केवल तभी करेंगे, जब लागत-लाभ गणना सभी आयामों में निर्णायक रूप से सकारात्मक होगी।"

भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी को आई-बैंकों पर निगरानी रखनी चाहिए

भारतीय रिज़र्व ने देश के निवेश बैंकों की गतिविधियों से सम्बन्धित सूचना में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे वित्तीय सुभेद्यता के संभाव्य कारण न बन जाएं - उनके द्वारा जारी अथवा उनकी मध्यस्थता में जारी किए गए वित्तीय उत्पादों के मामले में जोखिम पारदर्शिता के उच्चतर स्तर के साथ- अंतरंग बनाए जाने की पहली

बार मांग की है। इस समय भारत में पंजीकृत निवेश बैंक केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित होते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लाभों पर मंदी के विलंबित प्रभाव की चेतावनी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि आर्थिक मंदी का बैकों की ऋण गुणवत्ता और लाभप्रदता पर विलंबित प्रभाव हो सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि अपेक्षाकृत अत्यंत सुदृढ़ संभावना होने के बावजूद आर्थिक मंदी ने स्पष्ट रूप से बैंकिंग प्रणाली के तुलन पत्र में वृद्धि को कम कर दिया है। वैश्विक वित्तीय संकट की शुरूआत के समय तीव्र ऋण वृद्धि और तदुपरान्त गिरावट का आस्ति की गुणवत्ता पर कुछ दबाव पड़ा है। कुछेक पुनर्व्यवस्थित खातों में महत्वपूर्ण स्खलन (slippage) होने पर - जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, आस्ति की गुणवत्ता पर दबाव और बढ़ सकता है।

विशिष्ट घटनाएं

बजट ने कृषि ऋणों से सम्बन्धित प्रावधानीकरण का निवारण किया

सरकार द्वारा किसानों को ऋण चुकाने के लिए अधिक समय दिए जाने के परिणामस्वरूप सरकारी स्वामित्व के अधीन बैंक अपनी बहियों से सम्बन्धित अनर्जक आस्तियों को नियंत्रित रखने में समर्थ होंगे। इसके अलावा, सरकार से प्राप्त होने वाले ब्याज के रूप में एक अतिरिक्त सरकारी अनुदान से अब किसानों की ब्याजगत देयता पिछले वर्ष के 6 % के मुकाबले घट कर 5 % हो जाएगी। वर्ष 2010-11 के केन्द्रीय बजट में यह घोषणा की गई है कि खराब मानसून के बाद उनकी वित्तीय समस्याओं को कम करने के लिए किसानों को उनके ऋण चुकाने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय प्राप्त होगा। यदि उक्त राहत न प्राप्त हुई होती, तो बैंकों को अतिदेय कृषि ऋणों को चौथी तिमाही में अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विवश होना पड़ता। अब इस अतिरिक्त समय के प्राप्त हो जाने के परिणामस्वरूप ऐसे किसानों को, जो अपने ऋणों को वर्ष 2010-11 की पहली छमाही में चुका सकते हैं, चूककर्ता के रूप में नहीं वर्गीकृत किया जाएगा।

अनर्जक आस्तियों को निपटाने के लिए फेडरल बैंक ने टेण्डर जारी किए

अपने तुलन पत्र को स्वच्छ बनाने के अभियान के एक अंग के रूप में दक्षिण-भारत में स्थित फेडरल बैंक ने 80 करोड़ रुपये के मूल्य वाली समस्यामूलक आस्तियों को निपटाने के लिए टेण्डर जारी किया है। यह पहली बार है कि उक्त बैंक ने अपनी अनर्जक आस्तियों को आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (ARCs) को बेचने का कार्य आरंभ किया है। फेडरल बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री एम. वेणुगोपाल द्वारा

यथापुष्ट समाचार के अनुसार उक्त टेण्डर 15 मार्च को बंद हो गया तथा कीमत का निर्धारण सभी इच्छुक आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों से बोलियां प्राप्त करने के बाद किया गया।

15

एएनजेड बैंक को भारत में पुन: शाखाएं खोलने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त हुई

भारत, मध्य-पूर्व तथा दक्षिण एशिया के अन्य भागों में कारबार को बेच देने के दस वर्ष बाद आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (ANZ) बैंकिंग समूह को भारत में शाखा खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से सिद्धान्तत: अनुमोदन प्राप्त हो गया है। प्रारंभ में, एएनजेड की योजना शीर्ष श्रेणी वाले कॉरपोरेटों और वित्तीय संस्थाओं के लिए कॉरपोरेट बैंकिंग आरंभ करने की है, जिसके बाद बाज़ार के अपेक्षाकृत उच्च वर्गों के लिए खुदरा बैंकिंग आरंभ की जाएगी। मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया में एएनजेड के परिचालनों तथा उनसे जुड़े ग्रिण्डलेज के निजी बैंकिंग कारबार को स्टैण्डर्ढ चार्टर्ड बैंक ने वर्ष 2000 में 1.34 बिलियन डालर में अधिगृहीत कर लिया था। इस रकम में 700 मिलियन डालर के सुनाम की रकम भी शामिल थी।

निजी बैंकों ने गृह और कार ऋणों की दरें बढ़ाईं

एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिन्द्रा बैंक ने गृह और वाहन (Auto) ऋणों से सम्बन्धित दरें बढ़ा दी हैं, जो बाज़ार में कठोरता का संकेत करता है। बाज़ार दरों के कठोर होने के बाद इन निजी बैंकों ने उधार दरों में 100 आधार अंकों जितनी वृद्धि कर दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि को बढ़ावा देने वाले कुछेक उपायों को क्रमिक रूप से वापस लेना आरंभ कर दिया है तथा यह संकेत दिया है कि वह दरों को बढ़ाने से हिचकिचाएगा नहीं।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड के भारतीय परिचालनों में 1 बिलियन डालर का निवल लाभ दर्ज

स्टैंडर्ड चार्टर्ड के भारतीय परिचालनों से होने वाला लाभ पहली बार 1 बिलियन डालर की सीमा पार कर गया है। कैलेंडर वर्ष 2009 के कर-पूर्व लाभ में 19 % की वृद्धि हुई, जिससे वह एक वर्ष पहले के 891 मिलियन डालर से बढ़ कर 1.06 बिलियन डालर हो गया। वास्तव में भारतीय परिचालन स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए सबसे बड़े लाभ के केन्द्र का रूप ले रहा है। हांगकांग, जो अब तक बैंक का सबसे बड़ा लाभ का केन्द्र रहा है और भारत में लाभ के बीच का अंतर घट कर वर्ष 2008 में 98 मिलियन डालर और वर्ष 2007 में 503 मिलियन डालर की तुलना में अब 2 मिलियन डालर रह गया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा इसे पहला भारतीय निक्षेपागार निर्गम (IDR issue) बनाते हुए इस वर्ष मई - जून माह के आसपास 750 मिलियन डालर से 1 बिलियन डालर की सीमा तक किसी भी मात्रा में रकम जुटाने के लिए भारतीय निक्षेपागार रसीद (IDR) बाज़ार का दोहन किए जाने की संभावना है।

गांवों को सौर-ऊर्जा चालित जीव-सांख्यिकीय एटीएम प्राप्त होंगे

एटीएमों को गांवों तक विस्तारित करने के लिए उद्यम लगाने हेतु पूंजी -निधि प्राप्त एक कम्पनी, वोर्टेक्स इंजीनियरिंग सौर-ऊर्जा चालित जीव-सांख्यिकीय (biometric) एटीएमों पर निर्भर होने का दावा करती है। इन एटीएमों के लिए वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं होती और उनकी रख-रखाव लागत मामूली होती है, क्योंकि वे कम बिजली का उपभोग करती हैं। वोर्टेक्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और निदेशक श्री वी.

विजय बाबू ने बताया है कि उक्त सौर-ऊर्जा चालित जीव-सांख्यिकीय का विकास आईआईटी चेन्नै के सहयोग से स्वदेशीय स्तर पर किया गया था। इन एटीएमों की कीमत 3 लाख रुपये प्रत्येक निर्धारित की गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने वोर्टेक्स के पास 18 करोड़ रुपये के मूल्य वाले 545 जीव-सांख्यिकीय एटीएमों के लिए आदेश दे रखा है, जिनमें से 300 एटीएम केवल सौर-ऊर्जा चालित होंगे। श्री बाबू ने बताया कि बिजली में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों और लम्बी अवधि वाली बिजली कटौतियों के कारण ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में एटीएमों की पैठ नहीं हो पाई है। देश में लगाए गए 45,000 एटीएमों में से एक-चौथाई से कम ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। देश में बैंक खाते रखने वाले लगभग 10 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं। बैंक शाखाओं की दृष्टि से 90,000 शाखाओं / बिक्री केन्द्रों में से लगभग आधे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

बलून बंधक (Mortgage) : एक ऐसा बंधक, जिसमें बंधक की अवधि के समाप्त हो जाने पर उस ऋण शोधन (ब्याज और मूलधन), की परिणति ऋण के संपूर्ण भुगतान में नहीं होगी, जिसका भुगतान नियमित रूप से किया गया हो। वह भुगतान, जो अवधि की समाप्ति पर भी देय मूलधन की रकम का निरूपण करता है, एकमुश्त बड़ा अंतिम भुगतान (Balloon Payment) कहलाता है। किसी बंधक का एकमुश्त बड़ा अंतिम भुगतान (balloon) करना ऋण परिशोधन भुगतानों को उक्त बंधक की अवधि की तुलना में एक अपेक्षाकृत लम्बी अवधि में पुनर्व्यवस्थित करना है।

शब्दावली

मूल दर

ऋणों का मूल्य-निर्धारण करने हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त एक दर। मूल दर फेडरल निधियों की दर अथवा लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर जैसी कतिपय सामान्यतया प्रयुक्त सूचकांकों में से किसी एक से निकाली जाती है तथा वह मूल उधार दर से अपेक्षाकृत कम होगी। जहां बैंक मूल दर पर जोखिम अंतर (Risk spread) प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वहीं वे उक्त दर से कम पर उधार नहीं दे सकते। मूल दर की गणना करने के लिए अपनाए जाने वाले सूत्र में जमाराशियों की लागत, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) से सम्बन्धित अपेक्षाओं और लाभ-मार्जिन प्रतिधारित करने

की आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। किसी विशिष्ट प्रकार के उत्पाद की परिचालन लागत और ऋण जोखिम के प्रीमियमों तथा ऋणों की अवधि के आधार पर अधिक मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

शेयर बाज़ार में क्रय-विक्रय की जाने वाली निधि (EFT)

शेयर बाज़ार में क्रय-विक्रय की जाने वाली निधि (EFT) प्रतिभूतियों के अन्तर्निहित आधार वाली एक ऐसी निधि होती है, जिसमें उदाहरण के लिए 30 ऐसे स्टॉकों का समावेश होता है, जो सेंसेक्स अथवा निफ्टी समूह में 50 स्टॉकों से बने होते हैं। शेयर बाज़ार में क्रय-विक्रय की जाने वाली निधियां शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध होती हैं तथा उन्हें शेयरों की भांति खरीदा और बेचा जा सकता है।

संस्थान (Institute) समाचार

सक्रिय प्रतिरूप कक्षाएं (LIVE Virtual classes)

इंस्टिट्यूट ने उन लोगों के लिए, जो आगामी जेएआईआईबी / सीएआईआईबी / डीबी एण्ड एफ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सक्रिय प्रतिरूप कक्षाओं (Live Interactive Virtual Education) की व्यवस्था की है। ये कक्षाएं 26 अप्रैल से 13 मई 2010 तक संचालित की जएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

संपर्क कक्षाएं

इंस्टिट्यूट आगामी जेएआईआईबी / सीएआईआईबी (मई / जून 2010) की परीक्षाओं के लिए चुनिंदा शहरों में संपर्क कक्षाओं का संचालन करेगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षाओं की अद्यतन जानकारी

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे मई / जून 2010 में आयोजित होने वाली विविध परीक्षाओं के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या 15 / दक्षिण / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 26वीं तारीख को प्रेषित करें।

बैंक क्वेस्ट अब समूल्य प्रकाशन हो गया है। अभ्यर्थी निम्नलिखित आरूप के माध्यम से उसके ग्राहक बन सकते हैं :

श्री / श्रीमती / कु. ---

सदस्यता संख्या--

बैंक क्वेस्ट की विद्यमान अभिदान सं. बीक्यू : ---

डाक का पता : ---

पिन :------------------- टेलीफोन संख्या : ------------------------- ई-मेल : ---------------------

1 वर्ष (4 अंक) 140 रुपये

2 वर्ष (8 अंक) 240 रुपये

मैं इसके साथ ------------ रुपये का मांग ड्राफ्टसं. -------------- दिनांक ----------------संलग्न कर रहा / रही हूं

दिनांक : ------------------------- हस्ताक्षर : ---------------------------

टिप्पणी :

1. अभिदान अधिकतम केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए ही स्वीकार किया जाएगा।

2. अभिदान "इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स" के पक्ष में आहरित मुंबई में देय मांग ड्राफ्ट द्वारा स्वीक किए जाएंगे तथा फार्म निदेशक, प्रशासन इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स "दि आर्केड", विश्व व्याप केन्द्र, 2री मांजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई 400005 को प्रेषित किए जाने हैं।

बाज़ार की खबरें

तिमाही औसत दरें

जनवरी से मार्च 2010 तक की तिमाही के लिए

मुद्रा	दर
अमरीकी डालर	45.9350
ब्रिटिश पौंड	71.7325
यूरो	63.7000
जापानी येन	50.5500
फ्रेंच फ्रैंक (CHF)	43.5050
आस्ट्रेलियाई डालर	41.5325
हांगकांग डालर	5.9175
सिंगापुर डालर	32.7525
कनाडाई डालर	44.1900

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

बाज़ार का आशुचित्र (रकम मिलियन रुपयों में)				
संकेतक	05 मार्च 2010	12 मार्च 2010	19 मार्च 2010	26 मार्च 2010
मुद्रास्फीति (%)	8.56 % (फरवरी 2010)	8.56 % (फरवरी 2010)	9.89 % (फरवरी 2010)	9.89 % (फरवरी 2010)
औसत चलनिधि समायोजन सुविधा प्रत्यावर्ती पुन: खरीद परिमाण	70,481	66,459	10,326	24,935
औसत चलनिधि समायोजन सुविधा पुन: खरीद परिमाण	0	0	0	0
औसत पुन: खरीद दरें (%)	3.05	2.80	2.70	2.73
10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल	7.9930	7.9744	7.8971	7.8391
1-10 वर्ष का अंतर (आधार अंक)	298	283	277	279

6 माह का वायदा प्रीमियम (%)	2.95	3.00	2.96	3.39
6 माह का अमरीकी डालर लिबोर (%)	0.38	0.39	0.41	0.44

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के न्यूज़लेटर, फरवरी, 2010

भारित औसत मांग दरें

3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0

02/03/10 03/03/10 04/03/10 05/03/10 06/03/10 08/03/10 10/03/10 15/03/10 18/03/10 19/03/10 20/03/10 23/03/10 25/03/10 26/03/10

विनिमय दर
अमरीकी डालर / भारतीय रुपया नियत एवं अंतिम

46.20
46.00
45.80
45.60
45.40
45.20
45.00
44.80
44.60
44.40
44.20 पूर्वान्ह 11.30 बजे

अपरान्ह 5.30 बजे

02-03-10	15-03-10	31-03-10

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूव स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व खण्ड, कफ परेड,
मुंबई - 400 005

टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91 - 22 - 2218 51 47 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल :iibgen@bom5.vsnl.net.in
वेबसाइट : www.iibf.org.in

आईआईबीएफ विज़न मार्च, 2010